राजस्थान रॉयल्स ने मुख्यमंत्री भजनलाल को गोल्डन टिकट दिया

जयपुर, 5 अप्रैल। राजस्थान रॉयल्स के नेतृत्व - मनोज बडाले, रंजीत बरठाकुर, जेक लश मैक्रम और राजीव खन्ना ने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मुलाकात की, और उन्हें एक स्पेशल गोल्डन टिकट प्रदान किया, जिससे उन्हें इस सीजन में रॉयल्स के सभी घरेलू

- **जयपुर में 13 अप्रेल को हो रहे आईपीएल के पहले मैच से पहले मुख्यमंत्री व खेल मंत्री को यह विशेष टिकट दिया गया है।**

मैचों में प्रवेश मिल सकेगा, जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल को आरसीबी के खिलाफ मुकाबले से होगी।

इस मीटिंग के दौरान, टीम की आईपीएल 2025 की तैयारियों पर भी चर्चा की गई और फैंस के लिए एक अविस्मरणीय स्टेडियम अनुभव बनाने के लिए डिज़ाइन की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी शेयर की गई। इस बीच, फैंस अब रॉयल्स के आरसीबी, एलएसजी और जीटी के खिलाफ़ घरेलू मैचों के लिए अपने टिकट बुक माय शो ऐप पर विशेष रूप से बुक कर सकते हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में 7 अप्रैल से बॉक्स ऑफिस खुल जाएगा, जिसके बारे में अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी।

जयपुर में होने वाले आईपीएल के मैचों के लिए राजस्थान रॉयल्स नेतृत्व ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को गोल्डन टिकट भेंट किया।

'डल्लेवाल जी आप अनशन समाप्त करें'

नयी दिल्ली, 05 अप्रैल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ बातचीत की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अनशन समाप्त करने की अपील की है।

चौहान ने शनिवार को सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा

- **केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठन से वार्ता चल रही है हम डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील करते हैं।**

कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पहले से तय तिथि के अनुसार चार मई को बातचीत होगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच उनकी मांगों को लेकर चल रहा बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने कहा, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अब अस्पताल से वापस आ चुके हैं और हम उनके अतिशीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वह अपना अनशन समाप्त करें।

'राजस्थान के लोगों के लिये मेरे जीवन में स्पैशल जगह है'

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर का जयपुर में भाजपा ने भव्य स्वागत किया

जयपुर, 5 अप्रैल। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर के जयपुर प्रवास के दौरान शनिवार को भाजपा की ओर से भव्य स्वागत अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। विधानसभा के पास स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के सभागार में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि राजस्थान ने मुझे बहुत प्यार

- **राहटकर ने कहा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न को शत-प्रतिशत धरातल पर उतारने का प्रयास मुख्यमंत्री भजनलाल ने किया है।**

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर शनिवार को जयपुर दौर पर आईं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

दिया है। यहां के लोगों की भावना को मैं महसूस कर रही हूँ और समझ भी रही हूं। राजस्थान जैसा प्यार, अपनापन, सादगी, परिवार का भाव देशभर में और कहीं नहीं मिलता है। यहां मेरा सभी से विशेष नाता है। कोई बडा भाई, कोई छोटा भाई, कोई छोटी या बड़ी बहन है। राजस्थान मेरा मायका है। यहां प्यार के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहां के लोगों के लिए मेरे जीवन में बहुत ही स्पेशल जगह है। यहां से जाना बस यूं है जैसे मेरी जिम्मेदारी बदली है। जिम्मेदारियां हम सभी की बदलती रहनी चाहिए। राहटकर ने कहा कि महिला आयोग की अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद नई भूमिका में महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हूं। भूमिका बदलती रहेगी, हम सभी को काम करते रहना है।

विजया राहटकर ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे निर्णय जनता के हित में किए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शत प्रतिशत धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान को मदन राठौड़ जैसे संत, मिलनसार, मधुरभाषी भाजपा अध्यक्ष मिले है, यह हम सभी का सौभाग्य है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राहटकर राजस्थानी संस्कृति की पहचान साफा पहनाया और कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने में ताई विजया राहटकर का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान भाजपा सह प्रभारी के तौर पर उन्होंने ने आम कार्यकर्ता के साथ मिलकर दिन रात कार्य किया।

अभिनंदन समारोह में विधायक श्रीचंद कृपलानी, सांसद मंजू शर्मा, भाजपा उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, सरदार अजयपाल सिंह, मोतीलाल मीणा, भाजपा महामंत्री श्रवण सिंह बगडी मौजूद थे। मेयर सौम्या गुर्जर, कुसुम यादव ने शॉल पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंटकर राहटकर का स्वागत किया।

माइक्रोसॉफ्ट की पचासवीं सालगिरह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के लिए धन्यवाद। मैं सुन रहा हूँ।"

अबुसाद चिल्लाती रही और कहा, सुलेमान और "पूरे माइक्रोसॉफ्ट" के हाथ खून से रंगे हैं। अबुसाद ने आगे भी चिल्लाते हुए कहा कि सुलेमान और "पूरे माइक्रोसॉफ्ट" के हाथ खून से रंगे है। उसने मंच पर एक केफियेह स्कार्फ भी फेंका, जो फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन का प्रतीक बन गया है। बाद में उसे कार्यक्रम से बाहर ले जाया गया।

दूसरी प्रदर्शनकारी, माइक्रोसॉफ्ट की कर्मचारी वानिया अग्रवाल, ने भी उत्सव में व्यवधान डाला। उस दौरान बिल गेट्स, बाल्मर और वर्तमान सीईओ सत्य नडेला मंच पर थे। ये तीनों व्यक्ति, जो माइकोसॉफ्ट के सी.ई.ओ. रह चुके हैं, 2014 के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में एकसाथ मंच पर थे। एसोसिएटेड प्रेस की एक जांच में इस साल की शुरुआत में पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट और ओपन ए.आई. के ए.आई. मॉडल्स का, हाल ही में गाज़ा और लेबनान के युद्धों के दौरान इज़राइली सैन्य कार्यक्रम के हिस्से के रुप में बमबारी लक्ष्यों के चयन लिए उपयोग किया गया था। इस खबर में 2023 में हुए एक इज़राइली हवाई हमले के बारे में भी विवरण था, जिसमें लेबनानी परिवार के सदस्यों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें तीन युवा लड़कियों और उनकी दादी की मौत हो गई।

फरवरी में, माइक्रोसॉफ्ट के पांच कर्मचारियों को इन अनुबंधों का विरोध करने के लिए सीईओ सत्य नडेला के साथ एक मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया था। फरवरी की घटना जहाँ एक आंतरिक बैठक थी, वहीं, शुक्रवार का विरोध कहीं अधिक सार्वजनिक था- इस कार्यक्रम में कंपनी के अतीत और भविष्य को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। कुछ कर्मचारियों ने शुक्रवार को कार्यक्रम के बाहर भी रैली की।

शुक्रवार को कम्पनी द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया, "हम हमारे सभी कर्मचारियों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर देते हैं। पर साथ ही यह भी कहते हैं कि अपनी बात इस तरह कहें कि कंपनी का बिज़नेस प्रभावित ना हो। अगर बिज़नेस प्रभावित होता है तो हम उस कर्मचारी को अन्यत्र नौकरी करने का विकल्प देते हैं।" माइक्रोसॉफ्ट ने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या वह आगे कोई कार्रवाई कर रहा है। अबुसाद ने एपी को बताया कि उन्होंने अभी तक कंपनी की तरफ से कुछ नहीं सुना है, लेकिन, जब वो घर पहुँचीं तो पाया कि वो अपना कंपनी वर्क अकाउन्ट नहीं खोल पा रही हैं, अपने विरोध के बाद। जिससे संकेत मिलता है कि शायद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट : जस्टिस वर्मा ने शपथ ली

हालांकि उन्हें अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है।

प्रयागराज, 05 अप्रैल। दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए जज यशवंत वर्मा ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश के चैंबर में उन्हें शपथ दिलाई गई। हालांकि उन्हें अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जब तक उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी नहीं हो जाती, उन्हें न्यायिक कार्यों से दूर रखा गया है। शपथ के बाद हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची में उनका नाम भी शामिल हो गया है। सूची में जस्टिस वर्मा का नाम 8वें नंबर पर है। आमतौर पर जहां जजों की शपथ सार्वजनिक समारोह में होती है, वहीं जस्टिस वर्मा ने सीजेआई की इजाजत से अपने चैंबर में ही शपथ ली। उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर जस्टिस यशवंत वर्मा के शपथ ग्रहण का विरोध किया। एसोसिएशन के सचिव विक्रांत पांडेय की तरफ से लिखे इस पत्र में कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को शपथ

- **इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शपथ ग्रहण का विरोध किया और आरोप लगाया कि उन्हें शपथ ग्रहण की सूचना तक नहीं दी गई।**

ग्रहण कराने से पहले बार एसोसिएशन को बताया नहीं गया। यहां तक कि हाईकोर्ट के ज्यादातर जजों को भी शपथ ग्रहण की सूचना नहीं दी गई। इस तरह का शपथ ग्रहण अस्वीकार है। चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग की गई कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य न सौंपें। आज के इस पत्र की कॉपी प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, कानून मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और लखनऊ बेंच के सभी न्यायाधीश को भेजी गई है।

पीछे रह गए लोगों की चिंता करने वाला समाज हमेशा आगे बढ़ता है: शेखावत

अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा (महिला प्रकोष्ठ) के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए केन्द्रीय पर्यटन मंत्री

जयपुर, 5 अप्रैल। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो समाज पीछे रह गए लोगों की चिंता करता है, वह हमेशा आगे बढ़ता है। हमें इस पर विचार करना होगा कि कैसे समाज के कमजोर लोगों को संबल प्रदान कर उन्हें भी आगे की कतार में खड़ा किया जा सकता है।

शनिवार को अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा, राजस्थान (महिला प्रकोष्ठ) के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा द्वारा प्रदत्त सृजन क्षमता हम सब लोगों के पास में है, जिसके आधार पर ही समाज

- **उन्होंने कहा, यह विचार करना जरूरी है कि कैसे कमज़ोर लोगों को आगे की कतार में खड़ा किया जा सकता है।**

ने प्रगति भी की है। उसको नए-नए तरीकों से आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे आने वाले पीढ़ी प्रेरित हो सकें।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समाज को व्यवसाय के नए क्षेत्रों में भी काम करने की जरूरत है। इस पर विचार करना होगा कि हमारे पैतृक व्यवसाय से आगे निकलकर हमारी आने वाली पीढ़ियां किस तरह नए क्षेत्रों के व्यसाय में समाहित हो सकती हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दृढ़ संकल्प वह ताकत होती है, जो किसी भी समाज में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। दो लोग मिलकर भी यह ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी और उनका समर्थन करना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की मुहिम को अगर, अधिक से अधिक समर्थन मिलेगा तो दूसरे लोग भी समाज में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की दिशा में प्रेरित होंगे, इससे न केवल व्यक्तिगत सम्मान बढ़ेगा, बल्कि समाज का सम्मान भी बढ़ेगा।

प्र.मंत्री मोदी को "श्रीलंका मित्र विभूषण" सम्मान

कोलंबो, 05 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को श्रीलंका सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'श्रीलंका मित्र विभूषण' से सम्मानित किया है। श्रीलंका की यात्रा पर गए मोदी को राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने शनिवार को कोलंबो में एक समारोह में 'श्रीलंका मित्र विभूषण' से

- **मोदी बैंकॉक से तीन दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका गए हैं। प्रधानमंत्री ने "श्रीलंका मित्र विभूषण" सम्मान के लिए राष्ट्रपति दिसानायके का आभार जताया।**

सम्मानित किया और इस सम्मान के प्रतीक पदक को उनके गले में पहनाया।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके द्वारा मुझे श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है। यह सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच गहरी मित्रता और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। मैं इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति, सरकार और श्रीलंका के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

मोदी तीन दिवसीय यात्रा पर बैंकॉक से शुक्रवार शाम को कोलंबो पहुंचे। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ, स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतिस्सा और मत्स्य पालन मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर सहित पांच शीर्ष मंत्री मोदी के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर उपस्थित थे।

कांग्रेस अधिवेशन के लिये तैयार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और ब्लू प्रिंट तैयार करना होगा। यह भी तय करना होगा कि गठबंधनों से डील करने की क्या योजना है तथा उन राज्यों में, जहाँ वह पिछड़ गई है तथा जहाँ पर क्षेत्रीय दलों और भाजपा ने उसके वोट बैंक पर कब्जा कर लिया है, वहाँ अपना राजनीतिक स्थान पुन: कैसे प्राप्त किया जाए।

मसौदा प्रस्ताव (ड्राफ्ट रैज़ोल्यूशन) को विस्तारित कार्यसमिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसकी बैठक 8 अप्रैल को हो रही है और जिसमें 169 नेताओं को आमंत्रित किया गया है।

पार्टी को पुनर्जीवित करने और इसके लिए क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, इस पर सी.डब्ल्यु.सी. में चर्चा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो सी.डब्ल्यु.सी. द्वारा पारित प्रस्ताव में इसे शामिल किया जाएगा।

अगले दिन, 9 अप्रेल को दिन भर विचार-विमर्श होगा और प्रस्ताव पर चर्चा होगी, अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के भाषण होंगे।

मूल रूप से यह एकदिवसीय सत्र है जो गुजरात के पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के साथ-साथ कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी के सौ वर्ष और सरदार पटेल के जन्म के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि दोनों ही महान नेता गुजरात के थे।

वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश व्यापी आंदोलन होगा

नई दिल्ली, 05 अप्रैल। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से पास हो गया है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। इसके खिलाफ कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल एक निंदनीय कृत्य है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक घातक है। इससे अनेक समस्याएं और मुद्दे पैदा होंगे। सरकार इसे वापस ले। लोकसभा और राज्यसभा में

- **ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा भी की**
- **बोर्ड ने विपक्षी दलों के रुख की सराहना की, पर नीतीश, चन्द्रबाबू नायडू, चिराग पासवान व जयंत चौधरी की आलोचना की व कहा उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।**

विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने पूरी सूझबूझ, तैयारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ विधेयक का विरोध किया। साथ ही मुसलमानों के रुख को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने रखा। विपक्ष का ये कदम सराहनीय है।

बोर्ड विपक्षी दलों के सभी प्रमुखों और सांसदों का विधेयक के विरोध में उनके रुख के लिए आभार व्यक्त करता है। उनकी संवेदनशीलता की सराहना करता है। हम आशा करते हैं कि विपक्ष भविष्य में भी विधेयक के विरोध में हमारे अभियान में सहयोग करेगा। हालांकि, भाजपा के सहयोगी दलों और उनके नेताओं खासकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का रवैया निंदनीय रहा है। बोर्ड ने आगे कहा, मुसलमानों ने उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को देखते हुए हमेशा उनका समर्थन किया है लेकिन उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, जिसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन दलों से जुड़े मुसलमानों को अपनी स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिए। इस धोखे के बाद उनका क्या स्थान होगा? मुसलमान होने के नाते उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, पूरे मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देना निंदनीय है। बोर्ड साफ करता है कि वह किसी भी दबाव, धमकी या गलत रवैये के सामने अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा।

'सरकार के बाद, सबसे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिस दिन लोकसभा में बिल पारित हुआ था उस दिन गांधी ने कहा था, यह आरएसएस, भाजपा और उनके सहयोगियों का संविधान पर हमला है। आज मुसलमानों को निशाना बनाया है। पर यह भविष्य में अन्य समुदायों पर प्रहार करने का उदाहरण बनेगा।'

'कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने एक अन्य आलेख शेयर किया, जिसमें कहा था कि कैथलिक चर्चों के पास वक्फ से भी ज्यादा ज़मीने हैं। उन्होंने कहा, जैसा कि स्पष्ट है, पहले एक अल्पसंख्यक समुदाय को निशाने पर लिया गया, अब दूसरे की बारी है। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल 2025की वैधता को चुनौती दी और कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिल में वक्फ सम्पत्तियों व उनके प्रबंध पर मनमाने प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि मुसलमानों की धार्मिक स्वायत्तता को कमज़ोर किया जा सके। यह याचिका वकील अनस तनवीर ने दायर की है। याचिका के अनुसार बिल में ऐसे प्रतिबंध लगाए गए है, जो अन्य धार्मिक एन्डाओमैंट्स में नहीं है।

राजस्थान कांग्रेस संगठन का ढांचा 50 जिलों के हिसाब से तैयार

ए.आई.सी.सी. ने राजस्थान कांग्रेस में 50 जिला इकाइयों के गठन की मंजूरी दे दी है

जयपुर, 5 अप्रैल। कांग्रेस सरकार में गठित नौ जिले भाजपा सरकार ने खत्म कर दिए, लेकिन राजस्थान कांग्रेस ने अपना संगठन का ढांचा 50 जिलों के हिसाब से तैयार कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी इसकी मंजूरी दे दी है।

कांग्रेस ने खत्म किए जिलों में भी पार्टी का संगठन जिले के हिसाब से ही बनाया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रस्तावित 50 जिलों को शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब प्रदेश में कांग्रेस के 50 जिलाध्यक्ष होंगे।

संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आदेश के अनुसार,

- **प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा तथा प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हाल ही, 50 जिले बनाने का प्रस्ताव लेकर दिल्ली गये थे।**

कांग्रेस संगठन ने 11 नए जिले बनाए हैं। उनमें कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, फलौदी, बालोतरा और सलूंबर है। इसके अलावा सीकर से नीमकाथाना को अलग कर संगठन के हिसाब से नया जिला बनाया है. भीलवाड़ा जिले से भी भीलवाड़ा शहर को अलग जिला बनाया गया।

जोधपुर शहर में जोधपुर शहर उत्तर और जोधपुर शहर दक्षिण मर्ज कर एक जिला बना दिया। वहीं जयपुर ग्रामीण को दो हिस्सों में बांट दिया-जयपुर ग्रामीण पूर्व और जयपुर ग्रामीण पश्चिम।

कांग्रेस संगठन में अब अजमेर ग्रामीण, अजमेर शहर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां,बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा ग्रामीण, भीलवाड़ा शहर, बीकानेर ग्रामीण, बीकानेर शहर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डीडवाना-कुचामन, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर ग्रामीण पूर्व, जयपुर ग्रामीण पश्चिम, जयपुर शहर शामिल है. इसी प्रकार जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं,जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा ग्रामीण, कोटा शहर, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, नीमकाथाना, पाली, फलोदी, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर जिले होंगे।

दरअसल संगठन में विस्तार और नए जिले बढ़ाने को लेकर पार्टी में लंबे समय से कसरत चल रही थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 50 जिले बनाने का प्रस्ताव लेकर दिल्ली गए थे और पार्टी शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में आग्रह किया था।

शिक्षक भर्ती पेपर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करीब दो साल से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं गोपाल सहारण की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। उसे सिर्फ मुख्य आरोपी भूपेन्द्र सहारण का भाई होने के कारण मामले में शामिल किया जा रहा है।

कटारा की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी पेपर लीक कांड में मुख्य भागीदार है। आरपीएससी सदस्य होने के कारण उसे प्रश्न पत्र बनाने का दायित्व सौंपा गया था। उसने तैयार प्रश्न पत्र को अपने घर लाकर अपने भांजे से रजिस्टर में उतरवाया। इसके बाद ही प्रश्न पत्र आगे वितरित किए गए। इसके अलावा गोपाल सहारण ने भूपेन्द्र सहारण से प्रश्न पत्र लेकर उसे पेपर हल करवाया। ऐसे में दोनों आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए। जिस पर अदालत ने दोनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।

सफल आवंटियों को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की पूरी राशि जमा करवा दी और इसे वापस भी नहीं लिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने 5 जुलाई 2013 को आदेश जारी कर सफल आवंटियों को पृथ्वीराज नगर योजना में ही भूखंड का पट्टा देने का आदेश दिया। इस आदेश को संशोधित करवाने के लिए जेडीए ने प्रार्थना पत्र भी दायर किया था, लेकिन अदालत ने 22 फरवरी 2024 को प्रार्थना पत्र खारिज कर पूर्व आदेश को बरकरार रखा। इस मामले में भी अदालत ने अप्रैल 2024 को फैसला देते हुए प्रार्थियों को इस संबंध में जेडीए के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कहा था।

जेडीए को भी कहा था कि वह पूर्व निर्णयों व कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रकरण को तय करे, लेकिन राज्य सरकार व जेडीए ने आदेश का पालन नहीं किया है। इसलिए दोषी अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

मामले पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

'जो भूमि "गैर कानूनी" तरीके ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में यह आरोप लगाने का मसाला दे दिया कि वक्फ की जमीनों के बाद सरकार की नज़र क्रिश्चियन्स की जमीन पर है।

ऑर्गनाइज़र का आलेख जो अब वापस ले लिया गया है, में दावा किया गया था कि देश में कैथलिक चर्चों के पास 7 करोड़ हैक्टेयर जमीन है और चर्च सबसे बड़े गैर सरकारी भूस्वामी हैं। आलेख में दावा किया गया है कि कैथलिक चर्चों की जमीनों की कीमत 20,000 करोड़ रु. है।

केन्द्र सरकार की लैंड इन्फॉर्मेशन वेबसाइट डेटा के हवाले से आर्टिकल में इस बात का खंडन किया गया है कि सरकार के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। उन्होंने कहा कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीनें कैथलिक चर्चों के पास हैं।"

'राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600